

परिश्रम और टेकनीक से यहां ही पैदा कर सकते हैं। वह विदेशी पूंजी को यहां पर आमंत्रित करके इस देश के गले को नागपाश में डालना चाहती है। यह सरकार आज देश के पूरे अर्थ-तंत्र को विदेशियों के हवाले कर रही है। कम-से-कम गांधी-जन्म-शताब्दी के साल में तो इस धारा को पलटना चाहिए, इस को बन्द करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी इस बात का आभास नहीं मिलता है।

विदेशों से इतना बड़ा कर्ज लेकर हमारे देश की बेकारी की समस्या हल नहीं हो पाई है। आज हालत यह है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है। 1961 में ग्रामीण क्षेत्र में 80 लाख बेकार थे, जो कि आज बढ़कर डेढ़ करोड़ हो गये हैं। अर्द्ध-बेकार और मौसमी बेकार इनके अलावा हैं। शहरी क्षेत्र में 1950-51 में निबन्धित बेकारों की संख्या 3,31,000 थी, जो बढ़कर 1967-68 में 27,40,000 हो गई है। क्या यह हमारी आर्थिक प्रगति की निशानी है? क्या यह हमारे आर्थिक संकट की समाप्ति का परिचायक है?

हमारे देश के नौजवान बड़ी उम्मीद, उद्गार और आशा के साथ स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं कि हम देश के निर्माता बनेंगे, हम देश का निर्माण करेंगे, लेकिन आज वे बेकारी के मुंह में जा रहे हैं। जब वे आन्दोलन करते हैं, तो हम उनको अनुशासन सिखाते हैं। अगर उनको अनुशासन सिखाना हो, तो पहले उन्हें रोजगार और काम देना होगा, उनकी बेकारी की समस्या को हल करना होगा। इसके बिना अनुशासन की बात उनके कानों में नहीं उतरेगी। आज बेकारों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। उस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, जब इस सरकार ने योजना को खत्म कर दिया है, विकास-कार्यों को ठप्प कर दिया है?

आज देहातों में बेकारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बड़े-बड़े हजारपतियों और लख-पतियों ने गरीब किसानों की जमीनों को खरीद-खरीदकर हड़प लिया है, जिससे बेजमीन और बेकार हो गये हैं। इस सरकार ने कहा था कि वह भूमि-सुधार करेगी, हद-बन्दी करेगी। उसने यह भी कहा था कि वह आमदनी की हद-बन्दी करेगी। लेकिन इस अभिभाषण में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। मालूम होता है कि सरकार ने उन नीतियों को छोड़ दिया है। जितने ही बड़े हजारीमल होंगे, उतना ही वे छूट-खसूट करके जमीन का केन्द्रीयकरण करेंगे। इस समस्या का एक-मात्र हल यह है कि सरकार इस छूट को बन्द करे, इन बेदखलियों को बन्द करे, उसने भूमि-सुधारों की जो घोषणा की थी, उसको कार्यान्वित करे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member should try to conclude in the couple of minutes. He has taken 20 minutes. There is not much time left for his group.

SHRI YOGENDRA SHARMA : I will need another five minutes. I should conclude on Monday.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right; he may resume his speech on Monday. There is very little time left for him.

15.36 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS FORTY-THIRD REPORT

SHRI BHALJIBHAI PARMAR (Dohad) : Sir, I beg to move :

"That this House do agree with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 20th February, 1968."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That this House agree with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and

Resolutions Presented to the House
on the 20th February, 1968."

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष
महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

That in the motion,—

add at the end—

"With the modification that further debate on the Constitution (Amendment) Bill, 1967 by Shri Nath Pai, as reported by Joint Committee, be adjourned and the Bill be taken up on a day or days allotted for the transaction of Government Business as the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, decide. The House further resolves that if any Rules need to be suspended to enable resumption of the discussion on the aforesaid Bill, the House shall proceed to do so before such resumption." (1)

पिछली बार जब इस विधेयक पर बहस चलाई गई, तो मैंने आपका ध्यान एक बुनियादी बात की ओर खींचा था। मैंने कहा था कि हमारा यह नियम है, यह परिपाटी है कि चार घंटे से अधिक समय किसी भी निजी सदस्य के विधेयक के लिए नहीं देना चाहिए। हाँ, दो दफ़ा इस तरह समय बढ़ाया गया है, लेकिन कभी भी किसी भी बिल के लिए 14 घंटे 20 मिनट का समय नहीं दिया गया है। समिति ने इस बिल के लिए जो समय दिया था, वह खत्म हो चुका है। आपने स्वयं कहा कि इसके बारे में अब निर्णय इस सदन को करना है। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैंने इस विधेयक के प्रस्तावक से भी बात की है और उन्होंने मेरे प्रस्ताव के मुख्य सिद्धान्त से अपनी सहमति व्यक्त की है।

वह सिद्धान्त बिल्कुल साफ़ है। स्थिति यह है कि निजी सदस्यों के करीब दो सौ विधेयक इस वक्त सदन के सामने हैं। अकेले मेरे 21 विधेयक हैं। इस विधेयक के प्रस्तावक

महोदय और अन्य माननीय सदस्यों के भी कई विधेयक हैं। दो साल हो गये, हम पखवाड़े में एक दिन, शुक्रवार, को सिर्फ इसी विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इस स्थिति को न तो प्रस्तावक महोदय, न मैं और न ही दूसरे माननीय सदस्य पसन्द करेंगे। हम उत्तरदायी हैं, अपने मतदाताओं के प्रति, जनता के प्रति। हम उनको क्या कहें ?

इस सम्बन्ध में मैं हाउस आफ कामन्स से कई उदाहरण दे सकता हूँ। वहाँ पर अभी-अभी डार्डवोर्स के बारे में एक विधेयक आया था। वहाँ पर तय किया गया कि सरकार उसके लिए अपने टाइम में से समय निकालकर देगी। मेरा खयाल है कि फांसी के बारे में भी एक विधेयक हाउस आफ कामन्स में आया था। उसके बारे में भी सरकार ने यह निर्णय किया कि चूँकि उस बिल में काफी लोगों की रुचि है, इसलिए वह उसके लिए समय अपने समय में से दे देगी।

मैंने सुना है कि फिर एक प्रस्ताव आ-रहा है कि इस विधेयक को दोबारा संयुक्त समिति के पास भेजा जाये। मैं उस सुझाव के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा यह प्रस्ताव पास होने पर यह सदन सीधे इस प्रथम समिति की रपट पर चर्चा करके इसके बारे में जो भी करना हो, वह कर सकता है। अगर यह सदन चाहता है कि यह विधेयक फिर संयुक्त समिति के पास जाये, तो मेरे प्रस्ताव में उसके लिए कोई बाधा नहीं है। मेरा प्रस्ताव सिर्फ यह बताना चाहता है कि अब निजी सदस्यों का समय इस विधेयक पर खर्च नहीं किया जायेगा और अगर सरकार चाहती है, तो वह इसके लिए अपना समय दे दे। यही मेरे प्रस्ताव का मतलब है। मेरी राय है कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, यह सर्व-सम्मति से पास होना चाहिए।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I support what has been said by Mr. Madhu Limaye.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : I have to say only one thing. I have no objection. As Mr. Madhu Limaye pointed out, in order to facilitate discussion of other Bills that are lying and since this Bill has support almost of the majority of the House, it is meet and proper that the House may fix a day or days, if necessary, to discuss the Bill and pass it. The proposal is acceptable to me only on one condition that let us fix a day or days, the number of hours, that we want to devote to this Bill during this very session, before this Budget session adjourns. Because we are giving time to them to fix a day, that does not mean that we shall leave it again to be postponed to some other session. With this appeal, with this suggestion, I have no objection if this amendment of Mr. Madhu Limaye is adopted.

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai) : I do not want to go into the historical parallels of the Parliaments of other countries. After all, we in this House need not go into the parallels of other countries for everything. We have got to conduct the business of Parliament on the basis of our convenience. This Bill is an important Bill. Everybody agrees that it is an important Bill which raises a certain fundamental question about the amendment of the Constitution, about the power of Parliament to amend Constitution.

Quite apart from other thing that other Bills are being blocked, this kind of piecemeal discussion once every fortnight robs the discussion of futility of it. The people cannot follow what somebody has said earlier. Therefore, even to do justice to the importance of the Bill, there must be continuous discussion. That is why I say that the Government also must see to it that the Bill is given the importance that it is due and the people also are made aware of what is the type of discussion that is going on in the Parliament so that they can intelligently follow it. After all, the Parliament functions before the entire people and, on such an

important issue, the people must be able to judge the conduct of the Members of Parliament & the Parliament as a whole. I do not bother about the technicality as to how it is to be done. That is not my concern. My only concern is that this Bill should be continuously discussed and the Government must find proper time for it

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I fear, I am rather doubtful about the position which is being sought to be created. That is why I expect a definite assurance from the Government without which I am not in a position to agree to the suggestion put forward. I say so because, in regard to this matter, we have been treated to a very delectable process. A long time ago, the Government accorded its support to the principles of the Bill and it was on the initiative of the Law Minister that the Bill was referred to the Joint Committee and that Joint Committee, under your distinguished leadership, went into the matter whichever way it could. After all, this matter has been hanging fire. I have been noticing that in the country, particularly, from certain quarters, a campaign against the principles of this Bill has been conducted and whatever smacks, even remotely, of dilatoriness is something which I am not ready to stomach.

I want to put this Government a question in a very straight-forward way. They should come forward, in view of their attitude which they have proclaimed unless they have changed it altogether out of deference to the friends of the Swatantra Party in particular—if they have done so, let them say so, let them not take shelter behind this kind of dilatory tactics—in the course of this session, as quick as ever, to fix some time for the discussion of the Bill and the conclusions of this matter. I cannot understand if after more than a year, we cannot make up our mind about it. I know some of our friends are bringing all sorts of question and calling the other parties nonsensical and monarchical-inclined and the rest of it. But it really beats me that after so much discussion, we cannot make up our mind.

I am not going to accept without demur the idea of a dilatory postponement of this matter so that it can really be indefinitely postponed. That is what I fear might be the game behind the whisperings that I happen to hear these days. I want to have a categorical assurance in regard to that.

श्री मधु लिमये : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ । सरकार जो भी रुख अपनाना चाहती है ले, मगर अब हमारे बिलों का समय आप बरबाद करेंगे तो हमारा सहयोग इस सदन में नहीं रहेगा । मैं आज गम्भीर चेतावनी देना चाहता हूँ । जो आपको करना हो वह करें । इसका क्या मतलब है ? हम यहाँ बेकार समय बरबाद करने आए हैं क्या ?

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : The very fact that the bill is dragging on for such a long time shows the indecision on the part of the Government, the embarrassed position in which Government finds itself probably, because we have been hearing various reports in the press and also from the members that the Government itself is not clear as to whether they are totally going to support it or they are going to have some kind of a modification and then only give their support. This Bill was already referred to a Select Committee.

Again the Government is thinking of referring it to an other committee, a newly constituted committee. We have already given our word to the Government that we are prepared to support their reference to a Select Committee. As far as this is concerned, there is no change, because, this being such an important issue, we would not like to hustle the Government. But, at the same time, the Government should realise the complication of the matter and should not go on dragging it even after this Session is over. As Shri H. N. Mukerjee pointed out, at least before the end of this Session, Government should be clear in its mind as to what stand they are going to take in regard to this Bill.

I am prepared to support Mr. Madhu Limaye's motion in this sense that reference to the Select Committee is not going to be hampered because of Mr. Madhu Limaye's motion. Mr. Madhu Limaye and all the members of this House have the legitimate right to say that our precious time is lost, the little time that we get every alternate Friday for moving Bills is lost. Certainly, this matter should have been taken up much earlier than today. So, I think, the motion moved by Mr. Madhu Limaye can be supported by Government and they can fix a day, and even if they feel like referring the matter again to a Select Committee, we have no objection to that.

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated—Anglo-Indians) : My friend, Mr. Limaye's amendment seems to become completely otiose in view of the impression that Government proposes—and I feel, very rightly—to remit this matter again to a Joint Select Committee. It would not take more than five minutes if Government brings forward this motion, and I think it is very necessary because... (*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : Why ? A Joint Select Committee has already reported.

SHRI FRANK ANTHONY : As you know, it is not only the Swatantra Party that has been agitated, but all the minorities have been deeply agitated about this proposal of the Government or Parliament to take power. You may be aware of the latest decisions of the Supreme Court—one was held on the 4th December and the latest on the 13th January. It changes the whole Constitutional complexion. So far, those who wanted to take power to expropriate your property or mine, hard-earned though it may be, were using article 31 as an excuse. The Supreme Court, in its wisdom, has completely denuded article 31 of all its content... (*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA : He is going into the merits.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are not supposed to go into the merits now...(*Interruptions*) In passing, he has mentioned.

SHRI FRANK ANTHONY : I am not going into the merits.

SHRI MADHU LIMAYE : Let him speak on the motion.

SHRI FRANK ANTHONY : It is very necessary for the matter to be remitted to a Joint Select Committee because...

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are just now considering Mr. Limaye's amendment regarding fixation of time.

SHRI FRANK ANTHONY : It is a piece of surplus, a waste of time. Let us vote on the question of reference to Select Committee.

SHRI BALRAJ MADHOK (South Delhi) : The suggestion of Shri S. N. Dwivedy is reasonable and I think this should be acceptable to everyone.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : The amendment contains a very reasonable request. But unfortunately, it has been complicated by certain suggestions made here and there without knowing exactly what Government are going to do. We know Government's intentions not from their mouth directly here on the floor of the House, but through newspapers which have been giving in the last one or two weeks reports containing all kinds of speculations about their intentions concerning this Bill.

Therefore, if you do not complicate Shri Madhu Limaye's amendment but simply accept it, as Shri Dwivedy has said, and get an assurance from them that two days or three days or six hours or seven hours will be allotted to this from government time, we will be quite satisfied.

I do not wish to go into the fallacies of the other arguments raised as I do not myself want to add to the complica-

tion. The point is very simple. If you postpone it, we have no objection, but do not postpone it eternally. Let Government say they are going to give time to this during this session and before we disperse in May, we will be considering this Bill. That is all we want. Let the Law Minister or someone else representing Government say so here.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : Shri Madhu Limaye has asked for having this debate on a day other than a non-official day. There is a good deal of strength in his argument, because all non-official business was being blocked on account of the discussion of this Bill. But while speaking about it, certain aspersions were made on Government.

SHRI MADHU LIMAYE : Who made them ?

SHRI GOVINDA MENON : Certain members, not he. I want to say that Government stick to what I said on its behalf earlier during the debate on this Bill, that Parliament should have the power to amend the Constitution including Part III thereof.

SHRI S. KANDAPPAN : Do not go into the merits.

SHRI GOVINDA MENON : Because this was raised by others.

SHRI MADHU LIMAYE : I did not raise it.

SHRI GOVINDA MENON : He did not ; others did. What Government would like to see—and we would be moving a motion—is that in the light of several things which have happened for example, there was this Judgment of the Supreme Court referred to Shri Anthony...

SHRI FRANK ANTHONY : Two Judgments.

SHRI GOVINDA MENON : and the... Report of the Joint Committee itself is materially different from the Bill introduced originally by Shri Nath Pai...

SHRI P. RAMAMURTI : Why not ? The Joint Committee has got that power.

SHRI GOVINDA MENON : It has the power. But with some portions of it. Government are not in agreement. For all these reasons and keeping in view the principle that the right to amend should be available to Government...

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya) : Parliament, not Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He meant Parliament.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : It was the supremacy of Parliament then; now it is the supremacy of Government; later it is going to be the Law Minister's supremacy.

SHRI GOVINDA MENON : Do not get excited over certain slips of the tongue.

SHRI PILOO MODY : You want to have complete control over our lives and you say we should not be excited ?

SHRI GOVINDA MENON : Do not get excited. What I meant was that Government stand by the position that Parliament should have the constituent power to amend the Constitution, all parts of it.

SHRI PILOO MODY : If he says 'Parliament', it is an eye-wash.

SHRI GOVINDA MENON : Government would like to see that Parliament ceases to be an eye-wash, and irrespective of party considerations, there should be a second look at the nature of the Bill in the context of the various factors to which I referred. That is the position of Government.

I regret very much that some suggestion was made by others that we are vacillating over the matter. We are not. But we have our own views.

AN HON. MEMBER : That is the impression.

SHRI GOVINDA MENON : That impression is wrong. (*Interruptions*) All that I say is that Government without departing from the principle which were stated earlier that Parliament should have constituent power, wants to have a second look.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : On a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What we are debating just how is not the Government's intention to move a motion; that was only incidentally referred to. The main point before the House is the amendment moved by Mr. Limaye and it is on that amendment that I should like to hear you.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : You have explained my point of order.

SHRI GOVINDA MENON : I referred to other things because other things came up during the discussion. I said that there was a good deal of weight in what Mr. Limaye said here. But Government also has its own difficulties because the time at the disposal of the Government is short and the agenda is very heavy. Therefore, an unconditional assurance that Government should find time for this Bill also from out of its own allotted time is very difficult to give. The motion made by Mr. Limaye is that the Speaker in consultation with the Leader of the House may consider the point raised by him... (*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : It will be obligatory for the Government to find time if it accepted that motion.

SHRI GOVINDA MENON : Not necessarily out of the Government time.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDI (Kendrapara) : The motion is very clear that time will be allotted by the Speaker in consultation with the Leader of the House. The objection that the Government have is that they could not provide any time out of their own. I have a proposal to make. We are sitting till the 16 May and it is this House that

[Shri Surendranath Dwivedy]

will have ultimately to decide how long it should sit. We may decide here and now that we shall sit till the 18th of May and that extended two days will be provided for the discussion on this Bill. Let us decide on that now.

SHRI GOVINDA MENON: I want to make the Government position very clear so that it may not be alleged later on that Government resiled from any assurances given here. Even for the transaction of Government business time is very insufficient. Therefore, an additional day may have to be found. It need not necessarily be 17 or 18 May. A Saturday in between may be found for this purpose.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): It should be referred to the Business Advisory Committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It will ultimately go to the Business Advisory Committee. What the hon. Minister says will also be kept in mind.

But it is not part of the motion. So, you accept the motion.

16 Hrs.

SHRI MADHU LIMAYE: Why this higgling and haggling?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): There should not be any higgling. This should be made clear, afterwards if the House says or the other party says we do not want to sit on a Saturday or we do not want an extra day, we do not want to get involved in it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: So, this motion we can accept, as amended? (*Interruption*) Do we accept the report?

SHRI GOVINDA MENON: With the reservation made by us.

MR. DEPUTY SPEAKER: I will put the amendment to the vote of the House.

SHRI NATH PAI rose—

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall conclude it now, Mr. Nath Pai.

(*Interruption*) We are accepting this amendment. That is all; as modified by this observation because it is left to the Speaker ultimately.

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada): What are the amendments? The wording is not clear.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will read out. I presume that you have read the recommendation of the Committee.

SOME HON. MEMBERS: No.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The motion is:

"That this House do agree with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 20th February, 1968."

The Amendment is "add at the end "with the modification that further debate on the Constitution (Amendment) Bill, 1967 by Shri Nath Pai, as reported by Joint Committee, be adjourned and the Bill be taken up on a day or days allotted for the transaction of Government Business as the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, decide.

The House further resolves that if any Rules need to be suspended to enable resumption of the discussion on the aforesaid Bill, the House shall proceed to do so before such resumption."

SHRI GOVINDA MENON: We agree to this, with the reservation that a non-official day may be fixed, on a Saturday, when this may be set as the business for the day. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do the Members agree?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: That, the Leader of the House and the Speaker have to decide. We have nothing to say.

MR. DEPUTY-SPEAKER: With this reservation they agree. Is that all right, or, is there any other resolution?

SHRI GOVINDA MENON: On a Saturday we will accept.

SHRI P. RAMAMURTI: Have the Government lost all confidence that this request will not be considered by the Speaker? Why is there so much higgling?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not that. It is a question of the pressure on time. I will take it that with this assurance, and reservation,.....

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, कम्पनी डोनेशन के बारे में दो बार वचन दिया गया लेकिन फिर भी वह नहीं किया।

AN HON. MEMBER: What is the assurance?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: There is no reservation.

SHRI NATH PAI (Rajapur): There should be a categorical assurance.

SHRI GOVINDA MENON: I want to bring my motion. *(Interruption)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your motion will come after the adoption of the report. Your motion is independent. When we take the Bill, that will come. Now, we are on the adoption of the report, and for that, there is an amendment.

SHRI THIRUMALA RAO: We want to know on what we are voting. Is there a proposal to send the Bill to the Select Committee or not?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I want to move an amendment to Shri Madhu Limaye's amendment, namely, that this matter be referred to the Business Advisory Committee...*(Interruption)*

SHRI MADHU LIMAYE: It is out of order.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: With the clarification made by the Government, *(Interruption)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will put the motion to the vote; that is, the amendment of Shri Madhu Limaye. The question is:

That in the motion, *add* at the end—

“with the modification that further debate on the Constitution (Amendment) Bill, 1967, by Shri Nath Pai, as reported by Joint Committee, be adjourned and the Bill be taken up on a day or days allotted for the transaction of Government Business as the Speaker may, in consultation with the leader of the House, decide. The House further resolves that if any Rules need to be suspended to enable resumption of the discussion on the aforesaid Bill, the House shall proceed to do so before such resumption.” (1)

The Motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the motion as amended:

“That this House do agree with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 20th February, 1968, as amended.”

The motion was adopted.

16.05 hrs.

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL*

(Insection of new section 121 B)

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is: